

राजीव कुमार उपाध्याय

बनाम.

श्रीकांत उपाध्याय और अन्य।

(2024 की आपराधिक अपील सं 4831)

19 दिसंबर 2024

[सी. टी. रविकुमार और संजय करोल, न्यायमूर्तिगण]

विचारणीय बिंदु

पीड़ित पर गंभीर आरोप लगाए गए और सार्वजनिक स्थान पर उन्हें निर्वस्त्र किया और उस पर हमला किया गया। न्यायालय इसे सभी के लिए समानता और न्याय के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता का उल्लेख करने और पुष्टि करने के अवसर के रूप में लेता है।

मुख्य - बिंदु

दंड संहिता, 1860-धारा 341, 323, 354, 354 बी, 379, 504, 506, 149 - चुडैल
(डायन) अधिनियम — धारा 3 और 4-पीड़ित पर जादू-टोना का आरोप लगाया गया था — उसने शारीरिक और मौखिक रूप से दुर्यवहार किया और उसके बाद निर्वस्त्र किया — 13 अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई-विचारण न्यायालय ने संज्ञान लिया — अभियुक्त व्यक्तियों ने प्राथमिकी को धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत रद्द करने की मांग की उच्च न्यायालय ने उक्त

याचिका के लंबित रहने के दौरान कार्यवाही पर रोक लगा दी — उक्त आदेश से व्यथित शिकायतकर्ता ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया:

अभिनिर्धारित: सुनवाई के दौरान, यह सूचित किया गया कि संज्ञान को रद्द करने की याचिका वापस ले ली गई थी— यह मामला 'सामान्य परिस्थितियों' में नहीं आता है, प्राथमिकी से पता चलता है कि पीड़ित, जिसका नाम उक्त व्यक्ति की गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से संशोधित किया गया है, पर गंभीर आरोप लगाए गए थे और सार्वजनिक रूप से उसे निर्वस्त्र कर दिया और उस पर हमला भी किया गया था, जो निस्संदेह उसकी गरिमा का अपमान है— किए गए कृत्यों ने अदालत की अंतरात्मा को हिला दिया है— भले ही आपराधिक विविध याचिका अब वापस ले ली गई हो, लेकिन यह अदालत इस बात से हैरान है कि उच्च न्यायालय ने अपने विवेक से इसे स्वीकार करने के लिए उचित कैसे देखा। अभियुक्त व्यक्तियों की कार्यवाहियों के विरुद्ध स्थगन— कार्यवाहियों पर स्थगन देने वाला न्यायालय औपचारिकता निभाते हुए स्थगन आदेश देने के लिए नहीं है—पक्ष और विपक्ष दोनों परिस्थितियों के योग की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या स्थगन के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है या नहीं, या दूसरे शब्दों में, क्या स्थगन की गैर—मंजूरी किसी तरह के पूर्वाग्रह पक्षकार आदि के लिए है।—अधिकारियों ने संवेदनहीनता दिखाई — प्राथमिकी में लिखा है कि अधिकारियों ने शिकायतकर्ता के प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया और उसे दं.प्र.सं. की धारा 156 (3) का सहारा लेना पड़ा

— एक और अजीब स्थिति तब आई जब 13 अभियुक्त व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति, जिसका नाम संयोग से पीड़ितों के खिलाफ शारीरिक या मौखिक रूप से कार्रवाई करने के रूप में सीधे सामने नहीं आया था, को मुकदमे के लिए भेजा गया — आरोप पत्र में किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया गया कि जांच अधिकारियों ने इस तरह की कार्रवाई क्यों की — हालाँकि, जैसा कि आरोप-पत्र में सामने रखा गया है, इसके विपरीत दृष्टिकोण रखते हुए एसीजेएम ने सभी अभियुक्तों पर मुकदमे चलाने के लिए भेजना उचित पाया — राज्य ने भी अभियुक्त के पक्ष में स्थगन देने वाले उच्च न्यायालय के कारणरहित आदेश पर आपत्ति उठाने का विकल्प नहीं चुना — सभी के लिए समानता और न्याय के आदर्शों को बनाए रखने की आवश्यकता है — गरिमा भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र का एक अमूल्य पहलू है, और इसकी रक्षा के लिए सभी कार्रवाई करना राज्य का कर्तव्य है — इस प्रकार, यह निर्देश दिया जाता है कि मामले को कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए संबंधित जिला न्यायालय की फाइल में रखा जाए — आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध चल रहे मुकदमे की कार्यवाही प्रतिदिन आधार पर आगे बढ़ाई जाएगी। [कंडिका 8,9,10,14,15,17,27]

भारत का संविधान — अनुच्छेद 21 — गरिमा

अभिनिर्धारित: गरिमा समाज में एक व्यक्ति के अस्तित्व के मूल में जाती है — कोई भी कार्य जो किसी अन्य व्यक्ति या राज्य के कार्य से गरिमा को कम करता है, संभावित रूप से भारत के संविधान की भावना के खिलाफ जा रहा है,

जो यह सुनिश्चित करके सभी व्यक्तियों की सुरक्षा की गारंटी देता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित की जाती है —विस्तार से, यदि किसी व्यक्ति की गरिमा से समझौता किया जाता है, तो उनके मानवाधिकार, जो उनके लिए मानव होने के कारण उपलब्ध हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के विभिन्न अधिनियमों द्वारा गारंटीकृत हैं, खतरे में हैं — गरिमा भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र का एक अमूल्य पहलू है और राज्य का कर्तव्य है कि वह इसकी रक्षा के लिए सभी कार्रवाई करे। [कंडिका 1 और 17] भारत के संविधान — अनुच्छेद 51 क — पर चर्चा की गई। [कंडिका 18-19]

न्याय दृष्टान्त

के. एस. पुट्टास्वामी (गोपनीयता-9 न्यायाधीश पीठ) बनाम भारत संघ (2017) 10 एससीआर 569 : (2017) 10 एस. सी. सी. 1 — का अनुसरण किया गया। विक्रम देव सिंह तोमर बनाम बिहार राज्य [1988] सप.1 एससीआर 755:1988 पूरक एस. सी. सी. 734; पवन कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य [2017] 3 एस.सी.आर.458:(2017) 7 एस. सी. सी. 780; बोधिसत्त्व गौतम बनाम सुभा चक्रवर्ती [1995] सप।6 एससीआर 731:(1996) 1 एस. सी. सी. 490 - पर भरोसा किया।

निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ [2018] 14 एससीआर 755:(2019) 2 एस. सी. सी. 703; केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य [1973] सप.1 एस. सी. आर 1:(1973) 4 एस. सी. सी. 225; एक्स 2 बनाम राज्य (दिल्ली का एन. सी.

टी.) [2022] 7 एस. सी. आर. 686:(2023) 9 एस. सी. सी. 433; फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम राज्य (यू. टी. दिल्ली का) [1981] 2 एससीआर 516: (1981) 1 एस. सी. सी. 608 — संदर्भित।

दृष्टान्त के लिए पुस्तकें और पत्रिकाएँ

आलम और राज, (2021) द एकेडेमिक जर्नी ऑफ विचक्राफ्ट स्टडीज इन इंडिया, मैन इन इंडिया खंड 97 अंक 21

वेबसाइटों की सूची

2019: [https://www.ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/](https://www.ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/custom/1653730573_CII%202019%20Volume%201.pdf)

[custom/1653730573_CII%202019%20Volume%201.pdf](https://www.ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/custom/1653730573_CII%202019%20Volume%201.pdf)

2020: [https://www.ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/](https://www.ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/post/16959885631653645869CII2020Volume1.pdf)

[post/16959885631653645869CII2020Volume1.pdf](https://www.ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/post/16959885631653645869CII2020Volume1.pdf)

2021: [https://www.ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/](https://www.ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/custom/1696831798CII2021Volume1.pdf)

[custom/1696831798CII2021Volume1.pdf](https://www.ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/custom/1696831798CII2021Volume1.pdf)

2022: [https://www.ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/](https://www.ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/custom/1701607577CrimeinIndia2022Book1.pdf)

[custom/1701607577CrimeinIndia2022Book1.pdf](https://www.ncrb.gov.in/uploads/nationalcrimerecordsbureau/custom/1701607577CrimeinIndia2022Book1.pdf)

मानवाधिकार परिषद का प्रस्ताव दिनांक 12 जुलाई 2021 को अपने 47 वें सत्र में पारित किया गया।

<https://documents.un.org/doc/undoc/gen/q23/007/84/pdf/q2300784.pdf>

अधिनियमों की सूची

नागरिक और संरक्षण अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (अनुच्छेद 6,7,10,17 देखें), महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर समझौता (प्रस्तावना, अनुच्छेद 2,5 देखें) और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (अनुच्छेद 1,3,5,7,12 देखें)।

मुख्य शब्दों की सूची

जादू-टोना; तोड़फोड़; हमला; शारीरिक शोषण; मौखिक दुर्व्यवहार; गरिमा; मानवाधिकार; मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार; मौलिक कर्तव्य; अंधविश्वास; निराधार विश्वास; महिलाओं का संरक्षण; शोषण।

प्रकरण से उत्पन्न

आपराधिक अपील अधिकारिता : 2024 की आपराधिक अपील संख्या 4831
2023 के सी. आर. एल. एम. संख्या 30562 में पटना में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

भंवर पाल सिंह जादोन, सुशील तोमर, संजीव मल्होत्रा, अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता।
संतोष कुमार, राजीव आर. मिश्रा, सुश्री सुरुचि यादव, आशुतोष यादव, मनीष कुमार,
दिव्यांश मिश्रा, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

फैसला

संजय करोल, न्यायाधीश

अनुमति दी गई

"एक लिंग का दूसरे के प्रति कानूनी अधीनता-अपने आप में गलत है, और अब मानव उत्थान के लिए मुख्य बाधाओं में से एक है; और यह कि इसे पूर्ण समानता की प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें एक तरफ कोई शक्ति और विशेषाधिकार नहीं है, और न ही दूसरी तरफ विकलांगता है।"

[जॉन स्टुअर्ट मिल, आन सब्जेक्शन ऑफ वीमेन (महिलाओं के अधीनता पर), अध्याय 1 (1869).]

1. गरिमा समाज में एक व्यक्ति के अस्तित्व के मूल में जाती है। कोई भी कार्रवाई जो किसी अन्य व्यक्ति या राज्य के कार्य द्वारा गरिमा को कम करती है, संभावित रूप से भारत के संविधान¹ की भावना के खिलाफ है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करके सभी व्यक्तियों की सुरक्षा की गारंटी देता है। विस्तार से, यदि किसी व्यक्ति की गरिमा से समझौता किया जाता है, उनके मानवाधिकार, जो उनके मानव होने के कारण उनके लिए उपलब्ध हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के विभिन्न अधिनियमों द्वारा गारंटीकृत हैं, खतरे में हैं।

2. हम के. एस. पुट्टास्वामी (गोपनीयता -9 न्यायाधीश पीठ) बनाम भारत संघ² में किये गए अवलोकनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं :

“108. पिछले चार दशकों में, हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र ने गरिमा के साथ जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच अविभाज्य संबंध को मान्यता दी है। संवैधानिक मूल्य के रूप में गरिमा की अभिव्यक्ति प्रस्तावना में मिलती है। संवैधानिक दृष्टिकोण न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) की प्राप्ति चाहता है; स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की); समानता (व्यक्तियों के साथ मनमाने व्यवहार के खिलाफ गारंटी के रूप में) और बंधुत्व (जो प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का आश्वासन देता है)। ये संवैधानिक सिद्धांत एक मानवीय और दयालु समाज की सुविधा के लिए एकता में मौजूद हैं। व्यक्ति संविधान का केंद्र बिंदु है क्योंकि व्यक्तिगत अधिकारों की प्राप्ति में ही समुदाय का सामूहिक कल्याण निर्धारित होता है। मानव गरिमा संविधान का एक अभिन्न अंग है। गरिमा के प्रतिबिंब मनमानी के खिलाफ गारंटी (अनुच्छेद 14), स्वतंत्रता के दीपक (अनुच्छेद 19) और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 21) में मिलते हैं।”

3. जब एक महिला के ऐसे अधिकारों को खतरा होता है, तो खतरा तुलनात्मक रूप से अधिक होता है, क्योंकि बड़ी छलांग और सीमा से प्रगति के बावजूद, जब समानता की

बात आती है, तो बहुत कुछ हासिल किया जाना बाकी है, खासकर जब ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बात आती है।

4. यह मामला कुछ परेशान करने वाले तथ्यों पर आधारित है। भारतीय दंड संहिता, 1860³ की धारा 341, 323, 354, 354 बी, 379, 504, 506, 149 और डायन (डायन) अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत आशुतोष कुमार, परितोष कुमार, रिशु कुमार, जीसू कुमार, सोनी देवी, निर्मला देवी, लखपति देवी, सच्चिदानंद उपाध्याय, रविकांत उपाध्याय, श्रीकांत उपाध्याय, असीम प्रियांशु, श्रीना उपाध्याय और शशीकांत उपाध्याय जैसे 13 व्यक्तियों के खिलाफ 04 मार्च 2020 को दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट⁴ 3 का विवरण है। कथित अपराध कारित करने का वर्णन करने वाले प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैं:

"1. वर्तमान शिकायत से पता चलता है कि शिकायतकर्ता की दादी.... गाँव जा रही थीं। जैसे ही वह विरोधी पक्ष के शशीकांत उपाध्याय के घर के सामने पहुंची, विरोधी पक्ष के शशीकांत उपाध्याय ने घेर लिया और कहने लगे कि आपने जादू-टोना करके मेरे बेटे को बीमार कर दिया है। वह बीमारी से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। आज आपको अपनी जादू-टोना वापस लेकर मेरे बेटे को ठीक करना होगा। इस पर उन्होंने कहा कि आपको अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए। मैं चुड़ैल नहीं हूँ। इस पर विरोधी पक्ष के श्रीकांत उपाध्याय ने अपने परिवार के

3 इसके बाद भा. दं. वि.

4 इसके बाद 'प्राथमिकी'

सदस्यों को फोन किया कि एक चुड़ैल आई है। इसका जादू-टोना को समाप्त करना होगा।

2. उसी की निरंतरता में, विरोधी पक्ष आशुतोष कुमार ने शिकायतकर्ता की दादी के बाल (झोंटा) खींचना शुरू कर दिया. और स्टूल (गंदगी) लाने के लिए कहना शुरू कर दिया क्योंकि डायन की जादू-टोना को मुक्त करना है। इस पर विरोधी पक्ष के परितोष कुमार एक पात्र (फोफी) में गन्दगी लाए और विरोधी पक्ष के रिशु कुमार ने शिकायतकर्ता की दादी का हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती परितोष कुमार ने शिकायतकर्ता की दादी के मुंह में गन्दगी डाल दिया. जिससे जगमस्ती कुंवर को उल्टी होने लगी और वह जमीन पर गिर गई। शोर सुनकर, जब आवेदक और गवाह उसे बचाने गए, तो शशीकांत उपाध्याय ने आवेदक को पकड़ लिया और विरोधी पक्ष के बहनोई ने उसे लात मारना और थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, जिससे वह गाली-गलौज करने लगा। जब लड़ाई के दौरान आवेदक को बचाने गई, तो उसे भी सभी विरोधी पक्षों द्वारा गंदी गालियां दी गईं और परितोष कुमार और जिशु कुमार ने उसकी साड़ी और ब्लाउज फाड़कर उसे अर्ध-नग्न कर दिया और सोनी देवी ने शिकायतकर्ता की सोने की सिकड़ी छीन ली।

3. कि विरोधी पक्ष की रीना देवी ने कहना शुरू कर दिया कि डायन को उसे नग्न बनाकर उसे गाँव में घुमाया जाना है। इस पर रविकांत उपाध्याय और असीम प्रियांशु ने आवेदक की दादी को साड़ी फाड़ कर अर्ध-नग्न कर दिया और जब उसे खींचना शुरू किया तो वहां मौजूद गवाह ने उसे बचा लिया। इसके बाद, सभी विरोधी पक्ष भाग गए।
4. कि समान इरादे वाले सभी विरोधी पक्ष ने आवेदक, आवेदक की दादी और..... और उपरोक्त सभी लोगों को पीटा और दुर्व्यवहार किया।
5. कि घटना के बाद, आवेदक जो बुरी तरह से घायल हो गया था, उसने अरेराज सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराया।
6. कि आवेदक ने स्थानीय पुलिस स्टेशन को घटना के बारे में सूचित किया लेकिन एस.एच.ओ. ने आवेदक की रिपोर्ट नहीं ली। इसलिए, आवेदक इस मामले को माननीय न्यायालय के समक्ष दायर कर रहा है।
7. कि न्याय के हित में शिकायत दर्ज करने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन गोविंदगंज को शिकायत भेजना आवश्यक है।

इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि आवेदक की धारा 156 (3) दं.प्र.सं. के तहत स्थानीय पुलिस

स्टेशन में आवेदन भेजकर प्राथमिकी दर्ज करने का
आदेश पारित किया जाए ताकि आवेदक को न्याय
मिल सके जिसके लिए आवेदक माननीय न्यायालय
का आभारी होगा।

एसडी/-

राजीव कुमार उपाध्याय, आवेदक।

13. कार्रवाई की गई: चूँकि उपरोक्त जानकारी मद में उल्लिखित अपराध(ओं) के
होने का खुलासा करती है:2

(1) मामला दर्ज किया और जाँच शुरू की: सुबोध कुमार एस. आई. (सब-
इंस्पेक्टर), गोविंदगंज या

(2) निर्देशित (आई. ओ. का नाम):, रैंक: एस. आई. (सब-इंस्पेक्टर)
जांच शुरू करने के लिए:”

ऊपर निकाली गई प्राथमिकी में दो पीड़ितों के नाम थे, हालाँकि, आरोपों की प्रकृति को
देखते हुए और *निपुन सक्सेना बनाम भारत संघ* में जारी निर्देशों के साथ, को ध्यान में
रखते हुए उनके नाम संशोधित किए जाते हैं।

5. पुलिस, जाँच के बाद, नं .129/2020 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)
के समक्ष 08 अगस्त 2020 को भा. दं. वि. की धारा 341,329 और 504 के तहत केवल

एक व्यक्ति, लखपति देवी के खिलाफ और कहा कि अन्य में से किसी को भी मुकदमे के लिए नहीं भेजा जाना था।

6. अभिलेख से पता चलता है कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट⁶ -प्रथम, 6 मोतिहारी ने उपरोक्त घटना का संज्ञान लिया। 21 फरवरी 2021 का उक्त आदेश अभिलेख में नहीं है। इस तरह के संज्ञान को सत्र न्यायाधीश, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के समक्ष चुनौती दी गई थी। 16 जुलाई 2022 के आदेश से पता चलता है कि एसीजेएम ने मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद न केवल लखपति देवी बल्कि प्राथमिकी में नामित अन्य सभी व्यक्तियों के खिलाफ भी संज्ञान लिया। सत्र न्यायाधीश ने संज्ञान के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
7. यह उपरोक्त पृष्ठभूमि में है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने धारा 482, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973,⁷ के तहत पटना में उच्च न्यायालय के समक्ष 2023 के आपराधिक विविध सं. 30562 को प्राथमिकता दी, जिसमें इसे रद्द करने की मांग की गई थी। 04 जुलाई 2024 के उच्च न्यायालय के आदेश को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना; राज्य के लिए विद्वान स.लो.अ. और सूचना देने वाले के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. सुना है।

3. स्वीकार्य ।

6 इसके बाद 'एसीजेएम'

7 इसके बाद 'दं.प्र.सं.'

4. इस आवेदन के लंबित रहने के दौरान, 2022 के आपराधिक संशोधन संख्या 94 में मोतिहार में पूर्वी चंपारण के विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के संचालन पर केवल याचिकाकर्ताओं के संबंध में रोक रहेगी।”

8. उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रोक से व्यथित, शिकायतकर्ता ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है। 26 नवंबर 2024 को सुनवाई के दौरान, विद्वान अधिवक्ता ने हमें सूचित किया कि संज्ञान आदेश को रद्द करने की याचिका 22 नवंबर 2024 को वापस ले ली गई थी।
9. सामान्य परिस्थितियों में, विचारण न्यायालय से अभियुक्त व्यक्तियों के मुकदमे के साथ तेजी से आगे बढ़ने का अनुरोध करके याचिका का निपटारा किया जा सकता था, यह देखते हुए कि अपराध 2020 के शुरुआती हिस्से में किया गया था, और अब हम 2025 के दरवाजे पर खड़े हैं, हालांकि यह मामला 'सामान्य परिस्थितियों' में नहीं आता है। प्राथमिकी जैसा कि ऊपर निकाला गया है, से पता चलता है कि पीड़ित, जिसका नाम उक्त व्यक्ति की गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से लिखा गया है, पर गंभीर आरोप लगाए गए थे और सार्वजनिक रूप से उसके कपड़े उतार दिए गए थे और उस पर हमला किया गया था, जो निस्संदेह उसकी गरिमा का अपमान है। उसके खिलाफ कुछ अन्य कार्य भी किए गए थे, जिनका हम फिर से उल्लेख करने से बचते हैं, जिसका पूरा विस्तार पहले से ही ऊपर निकाला गया है और क्योंकि वास्तविकता यह है कि ऐसे कार्य अभी भी 21वीं सदी के जीवन का एक हिस्सा हैं, एक ऐसा तथ्य है जिसने इस न्यायालय की अंतरात्मा को हिला दिया है। पीड़ित पर न केवल जादू-टोना करने का आरोप लगाया गया था, बल्कि उसके

साथ शारीरिक और मौखिक रूप से भी दुर्व्यवहार किया गया था। इस सारी गड़बड़ी के बीच मौजूद एक अन्य व्यक्ति के कपड़े भी उतार दिए गए और उसके गहने छीन लिए गए।

10. आगे बढ़ने से पहले, हम यह देख सकते हैं कि भले ही आपराधिक विविध याचिका अब वापस ले ली गई है, लेकिन यह न्यायालय इस बात से हैरान है कि उच्च न्यायालय ने अपने विवेक में, अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही के खिलाफ रोक लगाने को कैसे उचित माना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश के आपराधिक कानून के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता और यह धारणा अंतिम क्षण तक चलती है। फिर भी, मशीनरी को इतने कठोर और अनुचित तरीके से नहीं रोका जा सकता है। कार्यवाही पर रोक लगाने वाला न्यायालय यांत्रिक तरीके से रोक नहीं देता है। पक्ष और विपक्ष दोनों की कुल परिस्थितियों की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या स्थगन के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है या नहीं, या दूसरे शब्दों में, क्या स्थगन की गैर-मंजूरी किसी तरह पक्ष को पूर्वाग्रहित करने के लिए है, आदि।
11. जब किसी व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन करने वाले अपराधों की बात आती है, तो हमारे विचार में, जांचकर्ता और न्यायनिर्णायक अधिकारियों दोनों पर दी गई जिम्मेदारी सामान्य से अधिक होती है या जो आम तौर पर अन्य परिस्थितियों में उन पर डाली जाती है। इन दोनों अधिकारियों को शामिल मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, सामाजिक स्थितियों के बारे में जागरूकता, खेल की परिस्थितियों से उत्पन्न भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता और कुछ समय के लिए चेतना कार्रवाई का सार है और अंत में, लेकिन

यकीनन सबसे महत्वपूर्ण अभियुक्त और पीड़ित के लिए कानून का पत्र और न्याय के तराजू का संतुलन।

12. हम यह देखने के लिए विवश हैं कि यह मामला हमें जो स्वाभाविक और अपेक्षित लगता है, उसके बिल्कुल विपरीत है। प्राथमिकी, जैसा कि ऊपर निकाला गया है, दर्ज करती है कि अधिकारियों ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए शिकायतकर्ता के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया और उस उसको दं.प्र.सं. की धारा 156 (3) के तहत जाना पड़ा। एक और अजीब स्थिति तब आई जब 13 अभियुक्त व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति, जिसका नाम संयोग से सीधे पीड़ितों के खिलाफ शारीरिक या मौखिक रूप से कार्रवाई करने के रूप में नहीं था, को मुकदमे के लिए भेजा गया, यानी लखपति देवी और जिनके खिलाफ शिकायत/प्राथमिकी में सीधे आरोप लगाए गए हैं, उन्हें छोड़ दिया गया। आरोप-पत्र में किसी भी कारण का खुलासा नहीं किया गया है कि जांच अधिकारियों ने इस तरह की कार्रवाई क्यों की। यह रिकॉर्ड की बात है कि जांच के दौरान एकत्र की गई एक ही सामग्री के आधार पर, विद्वान एसीजेएम ने आरोप पत्र में दिए गए विपरीत दृष्टिकोण को लेते हुए सभी आरोपी व्यक्तियों को मुकदमे में भेजना उचित पाया। यह हमें यह सवाल करने के लिए प्रेरित करता है कि सामग्री का एक समूह ऐसी पूर्णतया विपरीत क्रियाओं को कैसे प्रकट कर सकता है।
13. यह एक सर्वविदित तथ्य है कि राज्य और केंद्र सरकार उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय के समक्ष सबसे बड़े वादी हैं। राज्य पक्षकारों द्वारा प्रतिदिन कई मामले दर्ज किए जाते हैं। इस बात के कई कारण हो सकते हैं कि राज्य न्यायालय के समक्ष विभिन्न मुद्दों और विषयों पर मुकदमा करने का विकल्प क्यों चुनते हैं, लेकिन राज्य की किसी भी

कार्रवाई का व्यापक उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। इस संबंध में *विक्रम देव सिंह तोमर बनाम बिहार राज्य*,⁸ का संदर्भ दिया जा सकता है।

“2. भारत एक संविधान द्वारा शासित एक कल्याणकारी राज्य है जो अपने नागरिकों के दिलों में गौरव का स्थान रखता है। यह समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा और कल्याण पर विशेष जोर देता है और इसके प्रावधानों में उल्लेखित संवैधानिक गारंटी के आधार पर उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना चाहता है। यह महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेष सम्मान दिखाता है, और समानता के सिद्धांत के व्यापक विचार के बावजूद यह कानून द्वारा उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाने पर विचार करता है। यह केवल तभी उम्मीद की जा सकती है जब एक प्रबुद्ध संवैधानिक प्रणाली एक ऐसे समाज के राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक शासन का प्रभार संभालती है, जिसने सदियों से महिलाओं को उनके अधिकार से बहुत कम स्थान पर निर्वासित होते देखा है। हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जब इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए प्रदर्शित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मानवीय व्यक्तित्व के अनुरूप जीवन की गुणवत्ता का हकदार है। मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। और, इसलिए, लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में, राज्य उन दुर्भाग्यपूर्ण महिलाओं और बच्चों की देखभाल के लिए प्रतिष्ठानों को बनाए रखने की आवश्यकता को पहचानता है, जो एक अपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के रक्षक हैं और जिनके लिए, इसलिए, उनकी

सुरक्षा और कल्याण के लिए आवश्यक प्रावधान किया जाना चाहिए। समान मानवता और कानून और व्यवस्था दोनों के लिए राज्य को ऐसा करने की आवश्यकता होती है।...”

14. दोनों महिलाओं को जो कुछ भी सहना पड़ा, उसकी अक्षीलता को देखते हुए, हम और कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के पक्ष में स्थगन देने वाले उच्च न्यायालय के गैर-भाषी आदेश पर हमला नहीं करने का फैसला क्यों किया। किसी मुद्दे पर मुकदमा चलाने का राज्य का निर्णय उस लाभ पर निर्भर नहीं होना चाहिए जो या तो राज्य के खजाने को या कहीं और प्राप्त हो सकता है, बल्कि यह अपने लोगों के भीतर कानून के शासन और सभी के लिए न्याय के प्रति सम्मान की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी से भी परिलक्षित होना चाहिए।
15. हमारे सामने की घटनाएं, साथ ही कई अन्य घटनाएं जो हमारे डेस्क पर आती हैं, हमें जमीनी हकीकत में जीवित रखती हैं कि समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए विधायी, कार्यकारी और न्यायिक कार्रवाई के माध्यम से कितना भी किया गया है, इस संदर्भ में महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए, इसका प्रभाव जमीनी स्तर तक नहीं फैला है। हम इस अवसर पर सभी के लिए समानता और न्याय के आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का उल्लेख और पुष्टि करते हैं।
16. निर्विवाद रूप से, संविधान का अनुच्छेद 21 इस अमानवीय घटना में हुए उल्लंघनों में सबसे आगे है। प्रसिद्ध मामला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य,⁹ में अभিনিर्धारित किया कि

गरिमा का अधिकार संविधान के मूल संरचना का हिस्सा है। हाल ही में, एक्स 2 बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)¹⁰ 10 मामले में 3-न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा कि गरिमा की अवधारणा संविधान और उसमें निहित अधिकारों की नींव है। फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम राज्य (दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश),¹¹ में इस न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार में मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। पवन कुमार में बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य,¹² में

“47. ...एक पुरुष की तरह एक महिला की भी अपनी जगह होती है। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उतनी ही समानता प्राप्त है जितनी एक पुरुष को है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी के अनुसार गरिमा के साथ जीने के अधिकार का छेड़छाड़ के अप्रिय कृत्य में लिप्त होकर उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। यह लैंगिक संवेदनशीलता और न्याय की मौलिक अवधारणा और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत एक महिला के अधिकारों को प्रभावित करता है। इसके अलावा यह एक महिला के अधिकार में एक लाइलाज सेंध लगाता है जो उसके पास संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत है। यह सोचने के लिए मजबूर किया जाता है कि इस देश में महिलाओं को शांति से रहने और गरिमा और स्वतंत्रता के साथ सशक्त जीवन जीने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती है। यह ध्यान में रखना होगा कि उसे

10 [2022] 7 एससीआर 686:(2023) 9 एससीसी 433

11 [1981] 2 एससीआर 516:(1981) 1 एससीसी 608

12 [2017] 3 एससीआर 458:(2017) 7 एससीसी 780

जीवन का अधिकार है और वह अपनी पसंद के अनुसार प्रेम करने का हकदार है। उसके पास एक व्यक्तिगत विकल्प है जिसे कानूनी रूप से मान्यता दी गई है। सामाजिक रूप से इसका सम्मान किया जाना चाहिए। कोई भी महिला को प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। उसे अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है।

...

48. सभ्य समाज में पुरुष वर्चस्ववाद के लिए कोई जगह नहीं है। भारत का संविधान महिलाओं को सकारात्मक अधिकार प्रदान करता है और उक्त अधिकार संविधान के अनुच्छेद 15 से बोधगम्य हैं। जब संविधान के तहत अधिकार प्रदान किया जाता है, तो यह समझना होगा कि इसमें किसी प्रकार की कोई नरमी नहीं है। एक आदमी को अपने अहंकार या उस मामले के लिए, मर्दानगी को एक आधार पर नहीं रखना चाहिए और सभ्यता की अवधारणा को नहीं छोड़ना चाहिए। अहंकार को कानून के आगे झुकना चाहिए। इस संदर्भ में समानता को संवैधानिक सिद्धांत का सारांश माना जाना चाहिए।...

17. उपरोक्त निर्णयों के संदर्भ से जो पता चलता है वह यह है कि गरिमा भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र का एक अमूल्य पहलू है और इसकी रक्षा के लिए सभी कार्रवाई करना राज्य का कर्तव्य है।

18. निस्संदेह गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। लेकिन इसके साथ-साथ, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह उन मतभेदों को दरकिनार करते हुए सभी के बीच सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे जो भारत जैसे विशाल और विविध देश में स्वाभाविक हैं। संविधान के अनुच्छेद 51क का संदर्भ दिया जा सकता है। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि नीचे दिए गए 51क (ड) में महिलाओं के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने का कर्तव्य माना गया है। इसमें लिखा है:

“51-क. मौलिक कर्तव्य।—यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा -

...

(ड) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है ;

...

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और जनार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।

...

19. इस स्तर पर, हम संविधान के अनुच्छेद 51 (ग) पर भी ध्यान दे सकते हैं जो राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने की जिम्मेदारी देता है। जहाँ तक भारत का संबंध है, सभी मनुष्यों के लिए गरिमा की रक्षा और भेदभाव से महिलाओं की सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत दायित्वों के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय

नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार वाचा (अनुच्छेद 6,7,10,17 देखें), महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय¹³ (प्रस्तावना, अनुच्छेद 2,5 देखें) और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (अनुच्छेद 1,3,5,7,12 देखें) का हस्ताक्षरकर्ता है। सीईडीएडब्ल्यू के कुछ प्रावधानों के नीचे पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा:

“ प्रस्तावना

...

यह याद करते हुए कि महिलाओं के खिलाफ भेदभाव अधिकारों की समानता और मानव गरिमा के सम्मान के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, अपने देशों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में पुरुषों के साथ समान रूप से महिलाओं की भागीदारी में बाधा है, समाज और परिवार की समृद्धि में बाधा डालता है और अपने देश और मानवता की सेवा में महिलाओं की क्षमताओं के पूर्ण विकास को और अधिक कठिन बनाता है।

अनुच्छेद 2 राज्य दल महिलाओं के खिलाफ उसके सभी रूपों में भेदभाव की निंदा करते हैं, सभी उचित साधनों से और बिना किसी देरी के महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने की नीति को आगे बढ़ाने के लिए सहमत होते हैं और इसके लिए निम्नलिखित कार्य करते हैं:

(क) अपने राष्ट्रीय संविधानों या अन्य उपयुक्त विधानों में पुरुषों और महिलाओं की समानता के सिद्धांत को मूर्त रूप देना, यदि अभी तक उसमें शामिल

नहीं किया गया है और कानून और अन्य उपयुक्त साधनों के माध्यम से इस सिद्धांत की व्यावहारिक प्राप्ति सुनिश्चित करना;

- (ख) उचित विधायी और अन्य उपायों को अपनाना, जिसमें प्रतिबंध भी शामिल हैं, जिसमें महिलाओं के खिलाफ सभी भेदभाव को प्रतिबंधित करना शामिल है।
- (ग) पुरुषों के समान आधार पर महिलाओं के अधिकारों का कानूनी संरक्षण स्थापित करना और सक्षम राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के माध्यम से भेदभाव के किसी भी कार्य के खिलाफ महिलाओं की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करना;
- (घ) महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के किसी भी कार्य या प्रथा में शामिल होने से बचना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक प्राधिकरण और संस्थान इस दायित्व के अनुरूप कार्य करेंगे;
- (ई) किसी भी व्यक्ति, संगठन या उद्यम द्वारा महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए सभी उचित उपाय करना;
- (च) सभी उपयुक्त उपाय करना, जिसमें विधि निर्माण भी शामिल है, ताकि उन मौजूदा कानूनों, विनियमों, परंपराओं और प्रथाओं में संशोधन या उनका उन्मूलन किया जा सके, जो महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव का कारण बनते हैं।

...

अनुच्छेद 5 राज्य पक्ष सभी उचित उपाय करेंगे:(क) पुरुषों और महिलाओं के आचरण के सामाजिक और सांस्कृतिक पैटर्न को संशोधित करना, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं और अन्य सभी प्रथाओं को समाप्त करने की दृष्टि से जो किसी भी लिंग की हीनता या श्रेष्ठता के विचार पर या पुरुषों और महिलाओं के लिए रूढ़िवादी भूमिकाओं पर आधारित हैं।

20. महिलाओं की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उपरोक्त दायित्वों को ध्यान में रखते हुए, अब हम मुख्य आधार की ओर मुड़ते हैं, जिसके आधार पर दो महिला पीड़ितों को परेशान किया गया और उन पर गंभीर हमला किया गया।
21. जादू-टोना, जिसमें पीड़ितों में से एक पर आरोप लगाया जाता है, निश्चित रूप से एक ऐसी प्रथा है जिसे त्याग दिया जाना चाहिए। इस तरह के आरोपों का एक लंबा अतीत रहा है, जिसका शिकार होने वालों के लिए अक्सर दुखद परिणाम होते हैं। जादू-टोना अंधविश्वास, पितृसत्ता और सामाजिक नियंत्रण के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, जिससे यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस तरह के आरोप अक्सर उन महिलाओं के खिलाफ लगाए जाते थे जो या तो विधवा या बुजुर्ग थीं। ऐसे आरोप लगाने के पीछे अनेक कारण स्वीकार किए जाते हैं— जैसे जाति-आधारित भेदभाव, सामाजिक मानदंडों की अवहेलना के प्रतिशोध आदि। इसका प्रभाव अत्यंत नकारात्मक होता है, जिससे अमानवीय व्यवहार, सार्वजनिक अपमान और कभी-कभी मृत्यु तक हो जाती है।¹⁴

14 आम तौर पर देखें, आलम और राज, (2021) भारत में जादू-टोना अध्ययन की अकादमिक यात्रा, मैग इन इंडिया खंड.97 अंक 21

एन. सी. आर. बी. के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट ¹⁵	जादू-टोना,	354-बी भा. दं. वि.
2019	102	11238
2020	88	10580
2021	68	11102
2022	85	9101

22. हालांकि ऊपर उल्लिखित संख्याएँ महत्वहीन लग सकती हैं, हालाँकि, रिपोर्ट की गई अमानवीय, अपमानजनक घटनाओं की संख्या चाहे जो भी हो, 102 या 85, उनमें से प्रत्येक संवैधानिक भावना पर एक धब्बा है। उन कई व्यक्तियों को अंधविश्वासों, अनुमानों और पूरी तरह से निराधार मान्यताओं के आधार पर निशाना बनाया गया और संभवतः उनका शोषण किया गया और दुर्व्यवहार किया गया, जो उस वैज्ञानिक प्रवृत्ति के खिलाफ है जिसे भारत के प्रत्येक नागरिक ने अपने भीतर और अपने समुदायों के भीतर भी बढ़ावा

15 2019- [HTTPS://डब्ल्यू.डब्ल्यू.एन.सी.आर.बी.गव.इन/अपलोड/नेशनलक्राइमेरिकार्सब्यूरो/कस्टम/1653730573](https://डब्ल्यू.डब्ल्यू.एन.सी.आर.बी.गव.इन/अपलोड/नेशनलक्राइमेरिकार्सब्यूरो/कस्टम/1653730573) _ सी. आई. आई.% 20 2019% 20 वॉल्यूम% 201।पीडीएफ
2020- [HTTPS://डब्ल्यू.डब्ल्यू.एन.सी.आर.बी.गव.इन/अपलोड/नेशनलक्राइमेरिकार्सब्यूरो/पोस्ट/16959885631653645869CII20](https://डब्ल्यू.डब्ल्यू.एन.सी.आर.बी.गव.इन/अपलोड/नेशनलक्राइमेरिकार्सब्यूरो/पोस्ट/16959885631653645869CII20) 20 वॉल्यूम 1।पीडीएफ
2021- [HTTPS://डब्ल्यू.डब्ल्यू.एन.सी.आर.बी.गव./अपलोड/नेशनलक्राइमेरिकार्सब्यूरो/कस्टम/1696831798CII2021](https://डब्ल्यू.डब्ल्यू.एन.सी.आर.बी.गव./अपलोड/नेशनलक्राइमेरिकार्सब्यूरो/कस्टम/1696831798CII2021) खंड 1 में।पीडीएफ
2022- [HTTPS://डब्ल्यू.डब्ल्यू.एन.सी.आर.बी.गव.इन/अपलोड/नेशनलक्राइमेरिकार्सब्यूरो/कस्टम/1701607577](https://डब्ल्यू.डब्ल्यू.एन.सी.आर.बी.गव.इन/अपलोड/नेशनलक्राइमेरिकार्सब्यूरो/कस्टम/1701607577) क्राइमिनइंडिया20 22 बुक 1। पीडीएफ

देने का आह्वान किया था। प्रस्तुत की गई दूसरी संख्या, यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 354-बी के तहत दर्ज की गई घटनाओं की संख्या बहुत अधिक है। बोधिसत्त्व गौतम बनाम सुभा चक्रवर्ती⁶ में अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत अपराध के संदर्भ में निम्नलिखित टिप्पणियां की:

“10. इस प्रकार बलात्कार केवल एक महिला (पीड़ित) के व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं है, यह पूरे समाज के खिलाफ अपराध है। यह एक महिला के पूरे मनोविज्ञान को नष्ट कर देता है और उसे गहरे भावनात्मक संकट में धकेल देता है। यह केवल अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से है कि वह समाज में खुद को पुनर्स्थापित करती है, जो बलात्कार के बारे में पता चलने पर उसे उपहास और अवमानना में देखता है। इसलिए बलात्कार सबसे घृणित अपराध है। यह बुनियादी मानवाधिकारों के खिलाफ एक अपराध है और पीड़ित के मौलिक अधिकारों, अर्थात् अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार का भी उल्लंघन है। कई नारीवादियों और मनोचिकित्सकों के लिए, बलात्कार एक यौन अपराध कम और महिलाओं को अपमानित एवं नीचा दिखाने के उद्देश्य से किया गया आक्रामक कृत्य अधिक है। दुर्भाग्यवश, बलात्कार कानून मामले के सामाजिक पहलू का ध्यान नहीं रखते हैं और कई मामलों में अक्षम हैं।”

23. हम कह सकते हैं कि निर्वस्त्र करने का अपराध भी इस तरह के गहरे अपमान के अधीन महिला के मनोविज्ञान पर समान प्रभाव डालने के रूप में योग्य होगा।

24. जादू-टोना की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, इस तरह के आरोपों की गंभीरता और गंभीर दुष्प्रभाव और उसके बाद क्या होता है, यह विश्व स्तर पर देखा गया है। अपेक्षाकृत हाल ही में मानवाधिकार परिषद का 12 जुलाई 2021 का प्रस्ताव अपने 47 वें सत्र में पारित किया गया, जिसका प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया है:

“1. राज्यों से जादू-टोना और धार्मिक हमलों के आरोपों से संबंधित हानिकारक प्रथाओं की निंदा करने का आग्रह करता है जिसके परिणामस्वरूप मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है;

2. राज्यों से जादू-टोना और अनुष्ठान हमलों के आरोपों से संबंधित मानवाधिकारों के उल्लंघन की हानिकारक प्रथाओं के उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने और सभी व्यक्तियों, विशेष रूप से कमजोर स्थितियों में व्यक्तियों की जवाबदेही और प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आग्रह करता है।

...

4. संबंधित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से राज्यों को, जादू-टोना और अनुष्ठान हमलों के आरोपों से संबंधित मानवाधिकारों के उल्लंघन की मात्रा में हानिकारक प्रथाओं के प्रति संवेदनशील सभी व्यक्तियों की सुरक्षा का समर्थन करने के लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलों को बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित करता है, जबकि यह ध्यान में रखते हुए कि सुरक्षा प्रदान करने में, स्थानीय संदर्भ पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है;

.....

6. यह बल देता है कि राज्यों को उन हानिकारक प्रथाओं, जो जादू-टोना आरोपों और अनुष्ठानिक हमलों से संबंधित मानवाधिकार उल्लंघन का रूप लेती हैं, तथा विभिन्न प्रकार के धर्म या आस्थाओं के वैध और विधिसम्मत अभ्यास के बीच सावधानीपूर्वक अंतर करना चाहिए, ताकि धर्म या आस्था को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने के अधिकार की रक्षा की जा सके — चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या समुदाय के साथ, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्ति भी शामिल हों।

7. मानवाधिकार तंत्रों को प्रोत्साहित करता है, जिसमें मानवाधिकार परिषद की प्रासंगिकता विशेष प्रक्रियाएँ और संधि निकाय शामिल हैं, कि वे जादू-टोना के आरोपों और अनुष्ठानिक हमलों से संबंधित हानिकारक प्रथाओं पर जानकारी संकलित और साझा करें तथा उनके मानवाधिकारों के उपयोग पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करें।

..."

(जोर दिया गया)

25. इस प्रस्ताव के बाद, मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के कार्यालय की एक रिपोर्ट परिषद को उसके 52 वें सत्र में प्रस्तुत की गई थी, जिसका शीर्षक था 'जादू-टोना और अनुष्ठान हमलों के आरोपों से संबंधित हानिकारक प्रथाओं में निहित मानवाधिकारों के

उल्लंघन और दुरुपयोग की स्थिति पर अध्ययन, साथ ही साथ कलंक।'¹⁷ जिस संदर्भ से यह न्यायालय संबंधित है, उसे देखते हुए 'महिलाएँ और लड़कियाँ' पर धारा निष्कर्षण के योग्य है:

“17. महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर समिति ने नोट किया है कि कुछ देशों में लगातार पितृसत्तात्मक मानदंड महिलाओं को उनकी प्रजनन भूमिका तक सीमित रखते हैं और हानिकारक प्रथाओं को वैध बनाते हैं, जिसमें जादू-टोना का आरोप लगाना और जादू-टोना करने का आरोप लगाने वाली महिलाओं और लड़कियों का सामाजिक बहिष्कार शामिल है। कथित तौर पर, जो महिलाएं लैंगिक रूढ़ियों को पूरा नहीं करती हैं, जैसे कि विधवाएं, निःसंतान या अविवाहित महिलाएं, उन्हें जादू-टोना और प्रणालीगत भेदभाव के आरोपों का खतरा बढ़ जाता है। अन्य हाशिए के समूहों में वृद्ध महिलाएं, विकलांग महिलाएं, ऐल्बिनिज़म वाले बच्चों की माताएं, स्वदेशी महिलाएं, अल्पसंख्यकों और निचली जातियों से संबंधित महिलाएं, अफ्रीकी मूल की महिलाएं और विविध यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान, लिंग अभिव्यक्ति और यौन विशेषताओं वाली महिलाएं शामिल हैं।

18. शोध से पता चलता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर अक्सर जादू-टोना के आरोप लगते हैं। जादू-टोना के आरोपी महिलाओं को

17 रिपोर्ट को यहां देखा जा सकता है: [//दस्तावेज़।एक.ओआरजी/डॉक/अनडॉक/जीन/जी23/007/84 पीडीएफ/जी2300784।पीडीएफ](#)

विभिन्न प्रकार की हिंसा का शिकार बनाया गया है, जिसमें पीटा जाना, जलाया जाना, निर्वस्त्र किया जाना, बलात्कार किया जाना, विकृत किया जाना, जिंदा दफनाया जाना और मार दिया जाना शामिल है। कुछ देशों में इस तरह के आरोपों के गंभीर परिणामों के कारण, यह सुझाव दिया गया है कि उन महिलाओं को बचाने और फिर से बसाने के लिए आपातकालीन प्रक्रियाएं लागू की जाएं, जिन्हें अपने समुदायों में जादू-टोना से संबंधित हिंसा का सामना करने का खतरा है। कुछ देशों में, महिलाओं को जादू-टोना या छल के आधार पर भी हिरासत में लिया गया है, अक्सर उन्हें भीड़ के न्याय से बचाने के बहाने। कुछ देशों में ऐसी महिलाओं के उदाहरण भी हैं, जिन्हें एक प्रणाली के माध्यम से "डायन शिविरों" में भेजा गया है जिसमें न्यूनतम उचित कानूनी प्रक्रिया का अभाव है और जिससे समाज में लौटने की संभावना अनिश्चित है।

19. महिलाओं को लक्षित करने वाले जादू-टोना के आरोपों के कई मूल कारणों को विशेषज्ञ परामर्श के दौरान रेखांकित किया गया था, जिसमें पितृसत्ता, सांस्कृतिक विश्वास और संघर्षों और गरीबी की संरचनात्मक चुनौतियों शामिल हैं। प्रतिभागियों ने जादू-टोना और अनुष्ठान हमलों के आरोपों से संबंधित अन्य कारकों पर भी चर्चा की। उदाहरण के लिए, उत्तराधिकार संबंधी प्रथाओं का मतलब है कि बिना बच्चों या बिना बेटों के बहुविवाह में विधवाएं और पत्नियां असुरक्षित हैं क्योंकि कई मामलों में

भूमि, घर और अन्य संपत्तियां पति के बेटों को अन्य पत्नियों या निकटतम पुरुष रिश्तेदार से मिलेगी। वित्तीय संसाधनों, ध्यान, रूप या बच्चों के लिए प्रतिस्पर्धा जादू-टोना के आरोपों को जन्म दे सकती है और ईर्ष्या के परिणामस्वरूप हिंसा के कृत्यों का कारण बन सकती है। परिवार या स्थानीय समुदाय में बीमारी और मृत्यु, साथ ही साथ अन्य दुर्भाग्य, महिलाओं के खिलाफ जादू-टोना और अनुष्ठान हमलों के आरोपों को भड़काने के प्रमुख कारक हैं। स्थानीय समुदाय में अजनबियों/नवागंतुकों का आगमन एक अन्य कारक हो सकता है। महिला एजेंसी और अधिकारों का दावा भी स्वतंत्र और सशक्त महिलाओं के खिलाफ जादू-टोना के आरोपों को जन्म दे सकता है।

20. जादू-टोना के आरोप में वृद्ध महिलाओं को कारावास, जबरन भुखमरी, "भूल भगाने" समारोहों को नुकसान पहुँचाने के लिए बताया गया है, जैसे कि उन्हें सीमेंट जैसे खतरनाक पदार्थों को खाने के लिए मजबूर करना, और जादू-टोना की स्वीकारोक्ति निकालने और दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने के उद्देश्य से उनके सिर में कीलें डालना। कुछ देशों में, ऐसी महिलाओं को उनके अपने बच्चों, परिवार और समुदाय के सदस्यों द्वारा छोड़ दिया जाता है और अक्सर राज्य वैकल्पिक देखभाल सुविधाएं प्रदान नहीं करता है। जादू-टोना या प्रतिशोध के हमलों के अत्यधिक डर के कारण, "चुड़ैलों" के रूप में लेबल किए गए लोगों को उनके समुदायों के

हाशिए पर निर्वासित कर दिया जाता है और दयनीय परिस्थितियों में रहते हुए "सुरक्षित" स्थानों में सीमित रहने के लिए मजबूर किया जाता है।

21. महिलाओं के खिलाफ भेदभाव उन्मूलन समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि राज्यों को बूढ़े महिलाओं पर जादू-टोना का आरोप लगाया जाता है, जिसमें धमकी, अलगाव, दुर्व्यवहार और हत्याओं के साथ-साथ उनके घरों और परिवारों से निष्कासन शामिल हैं, के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा का मुकाबला करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें पर्याप्त सजा दी जाए।

...

23. महिलाओं के खिलाफ भेदभाव उन्मूलन समिति ने जादू-टोना के आरोपों के आधार पर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा और हत्या की घटनाओं की जांच करने और भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता पर जोर दिया है; इस तरह के कृत्यों के अपराधियों को गिरफ्तार करना, मुकदमा चलाना और पर्याप्त रूप से दंडित करना; प्रासंगिक कानून के प्रवर्तन को मजबूत करना; और जादू-टोना के आरोपों को अपराधी बनाना, जबकि जादू-टोना को अपराध बनाने वाले प्रावधानों को निरस्त करना।

24. समिति ने जादू-टोना के आरोपों के नकारात्मक प्रभाव को उजागर करने, पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ-साथ समुदाय और ग्राम प्रमुखों और धार्मिक नेताओं को शिक्षित करने और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के हमलों की आपराधिक प्रकृति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रमों को शुरू करने के महत्व पर भी जोर दिया है। इसने विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया है जो जादू-टोना के आरोपी महिलाओं के मनोवैज्ञानिक आघात, शारीरिक नुकसान, सामाजिक बहिष्कार और निर्धनता को संबोधित करते हैं और पीड़ित सहायता संरचनाओं को पर्याप्त संसाधन आवंटित करते हैं।”

26. पिछले कंडिकाओं में, हमने विभिन्न प्रकार के कानूनों, न्यायिक घोषणाओं और अन्य प्रासंगिक साहित्य पर चर्चा की है, विशेष रूप से, जादू-टोना के आरोपों और सामान्य रूप से, भेदभाव और शोषण से महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। हम इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं कि हमारे समक्ष आरोपित निर्णय को बाद में वापस लेने से अमान्य कर दिया गया है; हालांकि, स्थिति की विशिष्टता और कथित कार्यों की अक्षीलता को देखते हुए, हमने उपरोक्त पाठ्यक्रम को अपनाया।

27. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं:

- (1) कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए मामले को संबंधित जिला न्यायालय की फाइल में रखा जाता है।
- (2) अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा प्रतिदिन के आधार पर चलेगा।

- (3) अभियुक्त व्यक्तियों को 15 जनवरी 2025 को विचारण न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया जाता है।
- (4) यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल किए गए अपराधों की जघन्यता को दर्शाती हैं और किसी भी तरह से अभियुक्त व्यक्तियों पर अपराध दोषारोपण नहीं करती हैं।
- (5) मुकदमा उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगा, लेकिन इस निर्णय में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

लंबित आवेदन/नों, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

मामले का परिणाम: अपील का निपटारा किया गया।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।